



एक नए शोध के अनुसार, लाखों साल पहले पूर्वी अफ्रीका के "स्काय आयलैंड" पहाड़ों का "साउथ ट्रंक" आज के साउथ ट्रंक के समान ही रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि, नन्ही सी रंगबिरंगी चिड़ियों का समूह 5 लाख या शायद 10 लाख वर्षों से एक ही गाना गा रहा है। नैक्टोरियायडाय फैमिली की "सनबर्ड्स", रंगबिरंगी और छोटे साइज की चिड़ियाँ हैं। हम्मिंगबर्ड से मिलती-जुलती और पराग खाने वाली ये चिड़ियाँ पूरे अफ्रीका और एशिया में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। पूर्व में इन्हें डबल कॉलर्ड सनबर्ड कहा जाता था। युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली, में इन्टिग्रेटिव बायोलॉजी के प्रोफेसर तथा म्यूजियम ऑफ वॉट्रिब्रेट ज़ूऑलॉजी के अध्यक्ष, राओरी बोवी, जो इस शोध के वरिष्ठ लेखक हैं, ने कहा, "ये छोटे-छोटे रत्न हैं जो अचानक आपकी नज़रों के सामने आ जाते हैं।" ईस्टर्न डबल-कॉलर्ड सनबर्ड, जिसे "स्काय आयलैंड सनबर्ड" भी कहते हैं, पूर्व अफ्रीका में मोजाम्बीक से कीनिया तक, ऊँचे पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। आसमान छूती इन पहाड़ियों ने लाखों वर्षों के लिए इस प्रजाति की विभिन्न आबादियों या वंशावलियों को एक दूसरे से आइसोलेट (विलाग) कर दिया। लेकिन, एक दूसरे के साथ कोई भी इन्टरब्रैन्ड (परस्पर क्रिया) नहीं होने के बावजूद, स्काय आयलैंड सनबर्ड्स की कई आबादियाँ बिल्कुल एक दूसरे के समान हैं, इनमें अन्तर करना मुश्किल हो जाता है। शोधकर्ताओं ने इन चिड़ियों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए, 2007 से लेकर 2011 तक ईस्ट अफ्रीका में 15 स्काय आयलैंड्स का दौरा किया और 6 अलग-अलग वंशावलियों की 123 सनबर्ड्स के गाने रिकॉर्ड किए। शोधकर्ताओं ने पाया कि, चिड़ियों की कुछ आइसोलेटेड आबादियाँ अभी भी वही गाना गाती हैं। इससे शोधकर्ताओं ने यह थ्योरी दी कि एक दूसरे से अलग होने के बाद भी इनके गानों में परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने पाया कि दो आबादियाँ, जो बहुत अधिक लंबे समय से अलग थीं, उन दोनों के गाने लगभग एक समान थे। पूर्व शोधों के अनुसार जिओलॉजिकल परिस्थितियों में बदलाव से चिड़ियों और उनके गानों में बार-बार परिवर्तन होते हैं। लेकिन ईस्ट अफ्रीका के पहाड़ों के पर्यावरण में अधिक बदलाव नहीं हुआ है जिसके कारण लंबे समय से चिड़ियों के गाने वही के वही हैं।

इस वर्ष अप्रैल से अगस्त तक 75 राज्यसभा सदस्य रिटायर होंगे

इनमें 13 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, जिनमें कपिल सिब्बल, चिदंबरम, आनंद शर्मा, ए.के. एंटनी., जयराम रमेश व अंबिका सोनी शामिल हैं

-रेणु मिश्र-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। राज्यसभा के 75 सांसद इस साल, 2022 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये सांसद इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त तक कई टुकड़ों में सेवानिवृत्त होंगे।

सेवानिवृत्त होने वाले इन सांसदों में, 13 सांसद कांग्रेस के हैं। इनमें से कितने लोग पुनः राज्यसभा में आ सकेंगे, यह बात कई कारणों पर निर्भर करेगी, जिनमें सन्निकट विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं।
राजस्थान के 4 राज्यसभा सांसद, इस वर्ष जुलाई में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये चारों सदस्य भाजपा के हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस इस समय राज्य में सत्तारूढ़ है, तथा अगर पार्टी एकजुट बनी रहती है तथा निर्दलीय विधायक इसके साथ बने रहते हैं, तो यह 4 में से 3 सीटें जीत सकती है। उस स्थिति में,

- राजस्थान से चार राज्यसभा सदस्य, के.आई. एल्फॉस, हर्षवर्द्धन सिंह डूंगरपुर, ओम प्रकाश माथुर व राम कुमार वर्मा हैं। पर कितनी सीटें इस बार भाजपा को मिलेंगी? संभवतया एक, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और अगर पार्टी संगठित रही और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला तो तीन सीटें कांग्रेस की झोली में जा सकती हैं।
- इसी प्रकार सात मनोनीत राज्यसभा सदस्य भी अप्रैल में रिटायर हो जायेंगे।

भाजपा को एक ही सीट मिलेगी। सेवानिवृत्त होने वाले राज्यसभा सांसद हैं- के.आई. एल्फॉस, हर्षवर्द्धन सिंह डूंगरपुर, प्रकाश माथुर तथा राम कुमार वर्मा।

राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे प्रतिष्ठित नेताओं में शामिल हैं- केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (कान्टक), पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (महाराष्ट्र), पूर्व केन्द्रीय मंत्री

कपिल सिब्बल (उत्तर प्रदेश), पूर्व केन्द्रीय मंत्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश), पूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री अंबिका सोनी (पंजाब) तथा जयराम रमेश (कर्नाटक)। निर्मला सीतारमण के अतिरिक्त, ये सभी सांसद कांग्रेस के हैं। इनके अलावा, महाराष्ट्र से चुने गये एन.सी.पी. सदस्य प्रफुल्ल पटेल तथा शिव सेना सदस्य संजय राजत भी सेवानिवृत्त होने वाले सांसदों में शामिल

हैं। वर्तमान मंत्रियों में, महाराष्ट्र से चुने गये पीयूष गोयल तथा झारखंड से चुने गये मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सेवानिवृत्त हो रहे अन्य प्रमुख सांसद हैं- बिहार से लालू यादव की पुत्री मीसा भारती तथा मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ पत्रकार एम.जे. अकबर।

दिलचस्प बात यह है कि, 7 मनोनीत सदस्य भी इस वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी भी शामिल हैं, जो नरेंद्र मोदी पर निरन्तर प्रहार करते रहते हैं।

यह देखना सचमुच बड़ा रुचिकर होगा कि, डॉ. स्वामी आर.एस.एस. के दबाव के फलस्वरूप, राज्यसभा में वापस लाये जाते हैं या फिर मोदी आर.एस.एस. की अवहेलना करते हुये, अपना स्वयं का निर्णय लेते हैं। अप्रैल में, 5 सांसदों के स्थान, पंजाब में खाली हो जायेंगे तथा अंबिका सोनी का स्थान (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा अभी ताकत की स्थिति के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है वैस्टर्न यू.पी. में

भाजपा ने पिछले चुनाव में 46.3 प्रतिशत वोट व 58 में से तरेपन सीटें जीती थीं इस क्षेत्र में

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 फरवरी। भाजपा का खुद का आंतरिक आकलन यह है कि, 58 विधानसभा सीटों वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को वर्ष 2017 जैसा शानदार प्रदर्शन करने की उम्मीद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मतदान होना है। प्रश्न यह है कि क्या इस क्षेत्र में भाजपा को जो नुकसान होगा वह वृद्ध स्तर पर होगा।

वर्ष 2017 में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ यहाँ की 58 में से 53 सीटें जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जबकि सपा, बसपा और आर.एल.डी. सहित सभी विपक्षी पार्टियाँ 5 सीटों पर ही सिमट गई थीं। इस क्षेत्र में भाजपा को सपा के 21 और बसपा के 22 प्रतिशत वोटों की तुलना में 46.3 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए थे। अब मुख्य चुनौतीकर्ता मानी जा रही सपा का प्रदर्शन तभी बेहतर हो सकता है यदि भाजपा के वोट शेयर में 15 प्रतिशत की अनुमानित कमी और साथ ही सपा के वोट शेयर में 15 प्रतिशत की वृद्धि का

- बसपा को 22 प्रतिशत तथा सपा को 21 प्रतिशत वोट मिले थे।

- पर, इस बार सामाजिक व राजनीतिक स्थिति फर्क है, तथा सपा मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी है। पर जब तक भाजपा के वोटों में 15 प्रतिशत की कमी न आये और सपा के वोट पन्द्रह प्रतिशत न बढ़ें, सपा "फिनिशिंग लाइन" को छू नहीं पायेगी।

- पर, यह भी सच है कि, अखिलेश अपने राजनीतिक पते बड़ी होशियारी से खेल रहे हैं।

- वो जानबूझ कर मुसलमानों को वैस्टर्न यू.पी. में ज्यादा टिकट देने के जाल में नहीं फंसे, सहारनपुर व मुजफ्फरनगर जिलों में उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया।

- साथ ही अपने मूल वोट बैंक, यादवों से कुछ दूरी बनाने का प्रयास किया, जिससे भाजपा का, अखिलेश शासन को "गुण्डा व माफिया" के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो रहा।

चुनावी गणित बैठ जाए। किसान आंदोलन, बेरोजगारी और

मंहगाई सहित कई कारकों के कारण पिछले पांच वर्षों में सामाजिक-

जैसलमेर ट्रक यूनियन की दादागिरी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इण्डिया (सी.सी.आई.) ने सानू खनन क्षेत्र से,

- कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इण्डिया ने ट्रक यूनियन के कामकाज की भर्त्सना की। सी.सी.आई. का कहना है कि, यूनियन किसी गैर यूनियन के ट्रक को माल ढोने का मौका नहीं लेने देती तथा निर्धारित माल ढोने की दर भी यूनियन ही तय करती है और लागू करती है।

सी.जे.डी. लॉजिस्टिक्स कम्पनी द्वारा किए जा रहे खनिज परिवहन में बाधा डालने को लेकर जैसलमेर की डम्पर ट्रक यूनियन की कटु आलोचना की है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुनील जाखड़ का पद गया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद सुनील जाखड़ (68) को, चुनाव प्रचार को दिशा एवं गति देने वाली चुनाव-प्रबन्धन समिति की अध्यक्षता के दायित्व से चुपचाप हटा दिया गया है।

- सुनील जाखड़ पंजाब की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे, पर अब यह जिम्मेवारी लुधियाना के रवनीत सिंह बिट्टू को सौंपी गई है।

- जाखड़ का पद जाने का कारण, मु.मंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाये जाने पर उनकी यह टिप्पणी थी कि, उनके मु.मंत्री न बनने का सबसे बड़ा कारण उनका धर्म था।

इस पद से उन्हें हटाए जाने का कारण था, उनकी यह टिप्पणी, कि उनका हिन्दू धर्म उनके मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में आड़े आ गया, जबकि अधिकांश पार्टी विधायक चरणजीत चिन्नी को नहीं, बल्कि उन्हें चाहते थे और मु.मंत्री पद का उम्मीदवार चन्नी को बनाया गया। जाखड़ को प्रचार समिति के अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठापूर्ण जिम्मेदारी दी

गई थी, जिसके फलस्वरूप राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को काफी खोज भी हुई थी, क्योंकि वे प्रचार-योजना का दायित्व स्वयं लेना चाहते थे। लेकिन पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने, विवादास्पद बयान देने के लिए उन्हें सजा दी, खासतौर से जब, रविवार को चन्नी को विधानसभा चुनावों में पार्टी का

मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने के बाद जाखड़ ने लुधियाना में टिप्पणी की थी कि, वो "सक्रिय राजनीति से बाहर" हो गये हैं।

चुनाव प्रचार योजना से जाखड़ को बाहर किये जाने की विधिवत घोषणा के बिना ही, लुधियाना सांसद रवनीत सिंह बिट्टू (46) को चुनाव-प्रबन्धन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केन्द्रीय स्कीम में राज्य सरकारों की भूमिका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। केन्द्र इस बिन्दु पर विचार कर रहा है कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में, केन्द्र तथा केन्द्र-राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के प्रबंधन व उपयोग में राज्य सरकारों की भूमिका समाप्त कर दी जाये। केन्द्र का कहना है कि ऐसा करने से फण्ड के वितरण में प्रशासकीय अवरोध एवं अड़चनें खत्म हो जायेंगी। वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रायः फण्ड के वितरण में विलम्ब हो जाता है तथा राज्य सरकारों विभिन्न स्तरों पर वितरण को रोक देती हैं ताकि कुछ समय के लिये उस धनराशि को राज्य के प्रोजेक्टों के काम में ले सकें। इसलिए 500 करोड़ रु. से ज्यादा राशि की योजनाएं राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित नहीं की जायेंगी।

- वित्त मंत्रालय 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम का पैसा अब सीधे लाभाञ्चिता (बैंनिफिशियरिज़) के अकाउंट में भेजेगा। केन्द्रीय सरकार का मानना है, जब यह पैसा राज्य सरकारों के माध्यम से वितरित होता है तो, एक तरफ तो विलंब होता है तथा प्रशासनिक खर्चा बढ़ जाता है।

विचार यह चल रहा है कि एक नया "ट्रेजरी सिंगल अकाउन्ट" (टी.एस.ए.) मॉडल अपनाया जाये जिससे सम्बंधित योजनाओं के फण्ड सीधे लाभार्थियों तथा वैन्डर्स को ही जारी किए जायें। ये फण्ड भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहेंगे।

एक वर्ष में 500 करोड़ रु. से कम राशि की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकारें शामिल कर ली जायेंगी। राज्य सरकारें एक नियत कॉर्पोरेट बैंक में सेंट्रल नोडल खाता खोलेंगी, जहाँ से "सही समय" पर पैसा जारी किया जाता रहेगा, लेकिन कार्य-विशेष के लिये निर्धारित राशि की 25 प्रतिशत से अधिक राशि जारी नहीं की जा सकेगी तथा अतिरिक्त राशि तभी जारी की जायेगी, जब पहले जारी हुई राशि के 75 प्रतिशत हिस्से का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डेनमार्क नॉर्मल हुआ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 फरवरी। अगर जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो डेनमार्क की गिनती दुनिया के सर्वाधिक कोविड केस वाले देशों में है तथा वहाँ अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी अब तक की सर्वाधिक है। लेकिन, इसके बावजूद, डेनमार्क की सरकार ने सारे प्रतिबंध हटा दिये हैं। अब यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बंद स्थानों में भी

- सरकार ने कोविड से संबंधित सभी पाबंदियाँ, जैसे "मास्क" पहनना आदि, हटाईं।

मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है। यह कदाचित् सहजबुद्धि के विपरीत प्रतीत होता है, लेकिन देश के सत्ताधारियों का कहना है कि मृत्यु तथा अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या कोविड केसों की तुलना में काफी मन्द गति से बढ़ रही है तथा आई.सी.यू. में भर्ती मरीजों की संख्या पिछले महीने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नए लोग भी मंत्री-मुख्यमंत्री बनें, लेकिन पहले उनकी रगड़ाई जरूरी

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा, बुढ़ापे में राजनीति हमारे इन्टरैस्ट की बात नहीं है, सेहत के लिए जरूरी है

जयपुर, 9 फरवरी (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोकगहलोत ने एक बार फिर युवा नेताओं और कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की नसीहत दी और कहा कि जो युवा नेता-कार्यकर्ता राजनीति में आगे आ रहे हैं, उनकी रगड़ाई यानी ग्रूमिंग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो युवा संगठन में रहकर लम्बे समय तक रगड़ाई करवाकर कुर्सी पर आता है उसका व्यवहार, काम करने का तरीका, अनुभव सब अलग ही होता है। उन्होंने बुढ़ों को राजनीति के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि "बुढ़ापे में राजनीति करना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अतः हमें अंतिम सांस तक जनता की सेवा करने की जरूरत है।"

विधानसभा के नजदीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शिलान्यास कार्यक्रम में गहलोत कहा कि राजनेता अगर ज्यादा लोगों से मिल लेता है तो दुःखी हो जाता है और जब लोग उससे मिलने नहीं आते तब भी वह यह सोचकर दुखी होता है कि कहीं दुकान तो बंद नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देना चाहूंगा कि 75 साल के बाद नेता को घर बैठाने का उनका फैसला अच्छा नहीं है। कभी कांग्रेस में कामराज ने फैसला किया था कि 60 साल के नेता को राजनीति से निकाल दो। मैंने पता

किया है कि पहले के दौर में व्यक्ति की एवरेज उम्र होती थी 34 साल। वर्ष 1960 में जब कामराज जी ने फैसला किया तब एवरेज उम्र 40 होती थी। बाद में उम्र बढ़ती गई। अब औसत उम्र 70 साल है। यहाँ कई ऐसे मंत्री नेता बैठे हैं,

- राजनीतिज्ञ ज्यादा लोगों से मिलने से दुखी होता है, लोग मिलने नहीं आते तो भी दुखी होता है कि, कहीं दुकान तो बंद नहीं हो रही है।
- भाजपा विधायकों पर तंज किया, दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रखो कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिन्दा ना होना पड़े।

क्या हेमाराज चौधरी, शांति धारीवाल, गुलाबचन्द कटारिया, डॉ. सीपी जोशी जैसे नेता बूढ़े दिखते हैं। ये लोग 10 किलोमीटर रोज चलते हैं। एसेम्बली में और बाहर भी मुकाबला करते हैं। गुलाबचन्द कटारिया को राज्यपाल बना

दें तो बात अलग है। इसी के साथ उन्होंने राजेन्द्र राठौड़ से कहा "आप तो स्व. भैरों सिंह शेखावत के शगिर्द रहे हो। बताओ हम रिटायर हो जाएं तो कहाँ जाएं घर बैठ जाएंगे तो लोग मिलने भी नहीं आएंगे। आपको कह दें कि उम्र हो गई है, घर बैठ जाओ, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए यह हमारे इन्टरैस्ट की बात नहीं है, यह सेहत के लिए जरूरी है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। जिनगी जैसे नेता बूढ़े दिखते हैं। ये लोग 10 किलोमीटर रोज चलते हैं। एसेम्बली में और बाहर भी मुकाबला करते हैं। गुलाबचन्द कटारिया को राज्यपाल बना

कहा कि "कोई सीधा राज्यसभा में चला जाता है या बिना रगड़ाई करवाए आ जाता है तो उसके व्यवहार में बहुत अंतर होता है। मैं चाहता हूँ कि नए लोग भी मंत्री, मुख्यमंत्री सभी पदों पर आएँ। लेकिन उनकी ग्रूमिंग होना और उनका संगठन में काम करके आना जरूरी है।" गहलोत ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि "मैंने भी 40 साल रगड़ाई करवाई है।" उन्होंने वसुंधरा राजे के पहले ही बार मुख्यमंत्री बनने के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए बताया कि "तब एसेम्बली समाप्त होने पर राजे सभी युवा नेताओं को लेकर गहलोत ने